

दैनिक रोकठोक लेखनी

R

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र सियासी संकट से खड़े हुए सवाल? | मामला बड़ी बेंच को रेफर हो या नहीं, SC ने फैसला रखा सुरक्षित

हरीश साल्वे ने कहा- नबाम रेबिया केस को देखने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली : महाराष्ट्र सियासी संकट से उपजे सवालों के महेनजर मामला लार्ज बेंच भेजा जाए या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि मामले में एक मुद्दा ऐसा है जो कठिन संवैधानिक सवाल है जिस पर फैसला किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट में उद्घव ग्रुप की ओर से पेश सिनियर एडवोकेट कपिल सिंहल ने कहा कि नबाम रेबिया जजमेंट के मामले में उद्घव ग्रुप की ओर से पेश सिनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और एनके कौल पेश हुए और कहा था कि नबाम रेबिया केस को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा कि यह मामला अब सिर्फ अकेडमिक हो चुका है क्योंकि उद्घव ठाकरे का इस्तीफा हो चुका है। उन्होंने तब इस्तीफा दे दिया था जब उन्हें लगा था कि वह फ्लॉर टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने सवाल किया था कि नबाम रेबिया बनाम डिटी स्पीकर मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था उसे क्यों सात जज को भेजा जाना चाहिए? जिसके बाद सिंहल की ओर से दलील पेश की गई और कहा गया कि इसे सात जज को रेफर किया जाए। वहीं शिंदे ग्रुप इस दलील का विरोध कर रहे हैं।



चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा नबाम रेबिया केस में 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को लेकर भी है। रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर तब अयोग्यता कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते हैं जब उनको हटाए जाने का प्रस्ताव पेंडिंग है।

उद्घव ठाकरे गुट की ओर से पेश

सिनियर एडवोकेट कपिल सिंहल ने कहा था कि रेबिया केस में दिए गए जजमेंट को दोबारा देखने की जरूरत है। वहीं एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से सिनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और एनके कौल पेश हुए और कहा था कि नबाम रेबिया केस को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा कि यह मामला अब सिर्फ अकेडमिक हो चुका है क्योंकि उद्घव ठाकरे का इस्तीफा हो चुका है। उन्होंने तब इस्तीफा दे दिया था जब उन्हें लगा था कि वह फ्लॉर टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने सवाल किया था कि नबाम रेबिया बनाम डिटी स्पीकर मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था उसे क्यों सात जज को भेजा जाना चाहिए? जिसके बाद सिंहल की ओर से दलील पेश की गई और कहा गया कि इसे सात जज को रेफर किया जाए। वहीं शिंदे ग्रुप इस दलील का विरोध कर रहे हैं।

महाराष्ट्र सियासी संकट से उपजे सवालों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम

प्यार की सजा मौत! शादी करने की जिद कर रही थी महिला, सिक्योरिटी गार्ड ने कर दी हत्या



नवी मुंबई : महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड ने एक महिला की हत्या कर उसके शव को झाड़ियों में छिपा दिया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला उसकी प्रेमिका थी लेकिन वह उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। महिला से छुटकारा पाने के लिए आरोपी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिल्मात युलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और गई कि बरामद किया गया शव ट्रॉम्बे इलाके से गयब महिला का ही था। महिला के पति ने बताया कि वह मुंबई के मानसुन्दर इलाके के एक घर में साफ-सफाई का काम करती थी। महिला के फोन की डिटेल्स निकालने पर पुलिस को पता चला कि उसके राजकुमार बाबूराम पाल नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड से प्रेम संबंध थे।

खबर के अनुसार, बीती 12 फरवरी को पुलिस को नवी मुंबई के कोपरखैरने इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी के पास झाड़ियों में एक महिला का शव बरामद हुआ था। महिला की उम्र 35-40 वर्ष के बीच थी। महिला की ओढ़नी से गला

BBC के मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स का सर्वे खत्म, ट्रांसफर प्राइसिंग उल्लंघन के मिले सबूत - सूत्र



मुंबई : ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के मुंबई ऑफिस में आयकर विभाग 'सर्वे ऑपरेशन' गुरुवार शाम खत्म हो गया, जबकि दिल्ली बजाए से 'सर्वे ऑपरेशन' शुरू किया था, जो गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा।

हैं। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, जांच अधिकारियों को बीबीसी के मुंबई ऑफिस में ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों के उल्लंघन से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं। बता दें कि आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफतरों में मंगलवार करीब 11 बजे से 'सर्वे ऑपरेशन' शुरू किया था, जो गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा।

मनपा बजट में भाजपा के पूर्व नगरसेवकों के क्षेत्रों में धन की बरसात!

मुंबई : मनपा बजट में भाजपा के पूर्व नगरसेवकों के क्षेत्रों में धन की बरसात कर दी गई। हर भाजपा कॉरपोरेट के क्षेत्र में ३ करोड़ की निधि दी गई है, जबकि शिंदे गुट के नगरसेवकों में हर के क्षेत्र में सिर्फ एक करोड़ दिए गए हैं। ऐसे में इस कार्य पर यह कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती है कि अंथा बाटे रेवड़ी, अपनों को देता जाए।

राज्य में भाजपा की 'ईंडी' सरकार पर फिर भेदभाव का आरोप लगा है। मुंबई मनपा चुनाव के महेनजर भाजपा के पूर्व नगरसेवकों



वाले क्षेत्रों के लिए प्रशासन ने खास दरियादिली दिखाई है। भाजपा के पूर्व नगरसेवकों के क्षेत्र में धन की बरसात की गई है। भाजपा के हर पूर्व कॉरपोरेट को ३ करोड़ रुपए और शिंदे गुट के समेत अन्य पक्षों के प्रत्येक पूर्व नगरसेवकों के क्षेत्रों के लिए सिर्फ एक करोड़ रुपए फंड आवंटित करने का पैशसला किया गया है। लेकिन चहल पर भाजपा का दबाव खुलकर सामने आया है। मनपा के २०२३-२४ के बजट में २३१ करोड़ रुपए यानी भाजपा के ७७ पूर्व नगरसेवकों के वॉर्डों के लिए तीन-तीन करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि जिस शिंदे गुट

निधि मिली है जितनी विरोधी दलों के पूर्व नगरसेवकों को दी गई है। भाजपा के नगरसेवकों को छोड़कर अन्य सभी १५० पूर्व नगरसेवकों के वॉर्डों में प्रत्येक को १ करोड़ रुपए यानी १५० करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। चहल के इस पैशसले से बड़ा विवाद खड़ा होने की संभावना है। भाजपा ने बेशर्मी से इस फंड आवंटन की सराहना की है, जबकि शिवसेना और कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। मुंबई मनपा के नगरसेवकों का कार्यकाल गत ७ मार्च, २०२२ को समाप्त हुआ था।



संपादकीय / लेख



फैसल शेख

का राज्य में वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं होगा। निस्संदेह, इस फैसले के बाद विधानसभा चुनाव में किसी देरी को तारीक ठहराना अब केंद्र सरकार के लिये मुश्किल होगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण का आधार 2011 की जनगणना को बनाये जाने को लेकर अक्सर सवाल उठाये जा रहे थे। दलील दी जा रही थी कि परिसीमन प्रक्रिया 2026 में की जानी थी। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि केंद्र शासित प्रदेश में जनता को अपनी चुनी हुई सरकार देने की प्रक्रिया में अब और विलंब नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो दलील दी जायेगी कि केंद्र प्रदेश में वक्त पर चुनाव करवाने से वायदे से मुकर रहा है। यहां उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा व विधान सभा सीटों का परिसीमन करने वाले आयोग ने पिछले वर्ष मई में अंतिम रिपोर्ट में चुनावी नक्शों को फिर से तैयार किया था। इस नये परिसीमन के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में अब जम्मू के लिये छह और कश्मीर के लिये एक अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी। परिसीमन आयोग ने जो नया चुनावी प्रारूप तैयार किया है उसमें इस प्रदेश के लिये कुल विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। उल्लेखनीय है कि पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र की 24 सीटों को प्रतीकात्मक रूप से इसमें शामिल नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में पीडीपी तथा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लग गया था। जिसके चलते यहाँ चुनाव की प्रक्रिया सिरे न चढ़ सकी। कालांतर अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के बाद राजनीतिक अस्थिरता के चलते लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठहराव आ गया। अब एक बार फिर इस केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियाँ जोर पकड़ने लगी हैं। अब चुनाव की तिथियों को लेकर कथासाम लगाए जा रहे हैं। हालांकि, विगत में चुनाव करवाने को लेकर की गई तमाम भविष्यवाणियाँ सच की कसौटी पर खरी नहीं उतरी थीं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार बार-बार कहती रही है कि जब भी इस प्रदेश में सामान्य स्थिति और शांति बहाल होगी, निर्धारित अवधि के बीच स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना संभव हो सकगा। निस्संदेह, एक परिपक्व लोकतंत्र के लिये स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव करना अपरिहार्य ही है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। यदि कोई सरकार ऐसा करती है तो वह किसी पर अहसान नहीं कर रही होती है। अब केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सामान्य स्थिति लाने के लिये तत्काल प्रभाव से काम करना चाहिए। केंद्र को प्रदेश में विश्वास बहाली के लिये अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। जम्मू-कश्मीर के लोगों को मतदान करने का अधिकार यथाशीघ्र देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो यह प्रदेश की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने जैसा होगा। निस्संदेह, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बावजूद अनुमानों के अनुरूप प्रदेश में आतंकवाद का पूरी तरह सफाया नहीं हो सकता है। हाँ, उसकी आवृत्ति में कमी जरूर आई है। केंद्र व सेना की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टार्लरेस की नीति किसी हद तक कामयाब हुई है। छुटपट घटनाओं को अंजाम देने के अलावा चरमपंथी कोई बड़ा हमला करने में नाकामयाब रहे हैं। निस्संदेह, घाटी में फैले पाक पोषित आतंकवादी अपने आकाऊों के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतराने की कुत्सित कोशिशों को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार और सुरक्षाबलों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जायेगी।

 editor@rokthoklekhaninews.com

 Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

ठाणे के सहायक नगर आयुक्त के साथ मारपीट

पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड समेत आठ पर केस दर्ज



ठाणे : ठाणे शहर की पुलिस ने बुधवार देर रात एक सहायक नगर आयुक्त पर हमले के मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जिंटेंद्र आव्हाड समेत आठ पर हत्या के कथित प्रयास का मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारी ने उनके नाम का खुलासा किए बिना कहा कि चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी के खिलाफ आईंसीपी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

के कार्यकर्ताओं ने शाम करीब पैने छह बजे टीएमसी मुख्यालय के पास ठाणे नगर निगम के अतिक्रमण रोधी प्रकोष्ठ के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त महेश अहेर पर हमला किया और उन्हें धमकी दी। अधिकारी ने कहा कि कार्यकर्ता नाराज थे क्योंकि अहेर ने एक विक्रम खामकर के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की थी और आव्हाड के निर्वाचन क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को तोड़ दिया था। अहेर के बचाव में सुरक्षा गार्डों के आने के बाद मौके से पहले

पुलिस अधिकारी ने कहा कि
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)

कोस्टल रोड परियोजना में आ रही बाधाएं अब दूर... भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू !



ठाणे : पिछले कई सालों से कागजों पर लटकी कोस्टल रोड परियोजना में आ रही बाधाएं अब दूर हो गई हैं। मनपा ने इस परियोजना के तहत प्रभावित मैंग्रोव्ज (कांदलवन) क्षेत्र के बदले अब चंद्रपुर के एक गांव में १५ हेक्टेयर भूमि पर पुनरीपण करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव पर बन विभाग की सहमति के बाद अब मनपा प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि कई वर्षों से कागजों पर सिमटी कोस्टल परियोजना का काम अगले कुछ महीनों में शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ठाणे के गायमुख-खारेगांव कोस्टल रोड को लेकर पिछले कई सालों से चर्चा चल रही है। अब इस मार्ग में आनेवाली बाधाएं खत्म होती नजर आ रही हैं क्योंकि पिछले साल ही महानगर पालिका द्वारा इस कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार

की गई है। इस परियोजना के लिए एमएमआरडीए द्वारा निधि उपलब्ध कराई जाएगी। यह तटीय सड़क १३ किमी लंबी और ४५ मीटर चौड़ी होगी, जबकि इसका ५.५ किमी माग एलिवेटेड होगा। चूंकि यह तटीय सड़क सीआरजेड क्षेत्र से होकर गुजरती है इसलिए उस हिस्से में एलिवेटेड मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जबकि क्षेत्र में ४५० मीटर लंबी सड़क भूमिगत होगी। सलाहकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के लिए पर्यावरण विभाग कर्त्तव्य अनुमति की आवश्यकता होती है साथ ही बन विभाग व अन्य विभागों के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी जमाकराए जाएंगे। तदनुसार १,३१६.१५ करोड़ रुपए की संशोधित परियोजना रिपोर्ट एमएमआरडीए को पहले ही सौंपी जा चुकी है। घोड़बंदर रोड के समानांतर खारेगांव-गायमुख कोस्टल रोड निर्माण होने से भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी।

कमांडो की हत्या के आरोप में छह गिरफ्तार

गोंदिया जिले में भूमि विवाद को लेकर महाराष्ट्र के सी-60 बल के कमांडो विलास रामदास म्हस्के (41) की कथित रूप से हत्या करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सी-60 राज्य के गढ़चिराली और गोंदिया जिलों में नक्सल खतरे से निपटने के लिए बनाई गई एक विशेष लड़ाकू इकाई है। म्हस्के नवेंगांवबांध में तैनात थे। उनके परिवार का अजुर्नी मोरगांव तहसील में उन्हीं के गांव के एक पवार परिवार के साथ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। आरोप है कि पवार परिवार के सदस्यों ने धारदार हथियारों और लोहे की छड़ों से म्हस्के पर हमला किया, जिससे कमांडो की मौके पर ही मौत हो गई थी। सस्ता दरा पर दिलान का झासा देकर लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का पदार्थकार कर क्राइम ब्रांच की विराट यूनिट ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर तीन मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि जून 2021 से 28/03/2022 तक, पीयूष कुमार व अन्य लोगों को एक फर्जी कंपनी के ड्राइवर और आरोपी प्रवीण मल्हारी ननवरे, नितीन शर्मा, राहुल भट व अलायदा शहा ने बैंक द्वारा नीलाम की जा रही संपत्ति/मकानों को सस्ते में दिलाने का लालच दिखाकर उनसे 80 लाख रुपये ठग लिए। और इसके बाद फरार हो गए। पुलिस ने जाल बिछाकर चारों नामों को गिरफ्तार कर लिया है।

ਕਦੋਡੀਂ ਕੀ ਠਗੀ ਕਏਨੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ਾਤਿਰ ਮਹਾਉਣ ਗਿਆਪਤਾਰ



वसई : बैंकों द्वारा सीलबंद संपत्तियों / मकानों को सस्ती दरों पर दिलाने का झांसा देकर आम आदमी को ठगने वाले गिरोह के चार सदस्यों को क्राइम ब्रांच 3 विरार यूनिट ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 अपराधों का खुलासा भी किया है। जानकारी के अनुसार जून 2021 से 28/03/2022 दौरान शिकायतकर्ता पीयूष कुमार आनंदस्वरूप दीवान (56) और उसके साथ 44 अन्य लोग बोलिंज, विरार (पश्चिम) में हॉबिडर विनर्सहॉ पते के साथ एक फर्जी कंपनी के ड्राइवर और काल्पनिक नाम धारक आरोपी प्रविण मल्हारी ननवरे, नितीन शर्मा, राहुल भट व अलायदा शहा द्वारा बैंक द्वारा नीलाम की गई संपत्ति/मकान एन.पी.ए. सिद्धांत पर सस्ते समझोते बेचने का लालच दिखाकर उनसे कल 80 लार रुपये स्वीकार किया। उसके बाद कंपनी बंद कर फरार हो गए थे। अनार्ला सागरी पुलिस उक्त ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से सस्ते दामों पर बिक्री के लिए उपलब्ध फ्लैटों का विज्ञापन कर आम लोगों को ठगने वाला गिरोह सक्रिय था। मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच 3, विरार टीम ने गोपनीय मुखबिर से प्राप्त तकनीकी विशेषण और सूचना के आधार पर आरोपी परेवज दस्तगीर शेख ऊर्फ राहुल भट ऊर्फ पिटर सिक्कवेरा ऊर्फ आसिफ सैयद (31), साहेब हुस्सेन शेख ऊर्फ नितीन शर्मा ऊर्फ प्रशांत बन्सल ऊर्फ सोहल शेख (28), प्रविण मल्हारी ननवरे, खारेगाव व हिना इकबाल चुंडेसरा ऊर्फ अलायदा शहा ऊर्फ हिना सैयद को हिरासत में लिया।



नवी मुंबई के तुर्मे एमआई डीसी इथित कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग...



नवी मुंबई : मुंबई और ठाणे से सटे नवी मुंबई के तुर्मे एमआईडीसी के इंदिरानगर में आज शाम की रीब 5:55 बजे एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। जानकारी मिल रही है की कुछ मजदूर अंदर फँसे हुए हैं। आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। कपड़े का गोदाम के कारण कुछ ही देर में आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई और पूरे इलाके में धुआं फैल उठा है।

आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम कर रही हैं। बताया जा रहा है की कपनी को भारी नुकसान हुआ है। करीब तीन से चार

किलोमीटर दूर सायन-पनवेल हाईवे से आसमान में धुए के गुब्बारे उठते देखे जा सकते थे।

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है

आग बुझाने के लिए वाशी, नेरुल, सीबीडी और एमआईडीसी से 10 से 12 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। आग पूजा गारमेंट्स कंपनी में लगी। दमकल विभाग ने जल्दी से आग पर काबू पा लिया, जिससे आग पड़ोसी कंपनियों तक फैलने से रोका जा सका। इस बीच, इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है आगे की जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में एईआईटी-मुंबई के छात्र की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। उसके परिजनों ने इस घटना को हत्या करार दिया है। आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से होने की वजह से संस्थान में उसे भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ, मुंबई पुलिस ने कहा कि परिवार की आशंकों को भी मामले की विवेचना में शामिल किया गया है। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस ने छात्रावास पहुंच कर यहाँ रहने वाले अन्य छात्रों के बयान दर्ज किए। इन छात्रों से पुलिस ने विभिन्न एंगल पर सवाल पूछकर घटना के तह तक जाने की कोशिश की।

पुलिस ने मामले की शुरूआती जांच के बाद कहा कि छात्र दर्शन सोलंकी (18) ने रविवार को अपनी जान लेने से पहले कीरीब 30 मिनट तक अहमदाबाद में अपने पिता से बात की थी। पुलिस ने बताया कि अभी तक संस्थान में जातीय भेदभाव के बारे में कोई तथ्य सामने नहीं आया है। उधर, मुंबई में पवर्स्ट्री स्थित संस्थान ने पक्षपात के आरोपों को खारिज किया। वहाँ छात्रों से पुलिस और अंतरिक जांच



खत्म होने तक इंतजार करने का आग्रह किया है।

बता दें कि दर्शन सोलंकी (18) की रविवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के पवर्स्ट्री से एक छात्रावास की इमारत की सातवीं मजिल से कथित तौर पर छलांग लगाने से मौत हो गई थी। वह अहमदाबाद का रहने वाला था और बी.टेक (केमिकल) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष का छात्र था। दर्शन सोलंकी का परिवार अहमदाबाद शहर के मणिनगर इलाके में रहता है। परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि दर्शन को दिलत होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। वह आत्महत्या नहीं कर सकता था।

मां ने लगाया हत्या का आरोप
दर्शन की मां तरलिकाबेन सोलंकी ने कहा कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं

कर सकता है, उसे आशंका है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के कुछ घटे पहले उसने हमें फोन किया था लेकिन उसने सामान्य रूप से बात की और ऐसा कोई सकेत नहीं दिया कि वह किसी तनाव में है। हालांकि जब वह मकर संक्रान्ति के दौरान घर आया था तो उसने अपनी चाची को बताया था कि अन्य छात्र उससे दूरी बना रहे हैं। वे इसलिए विश्वास्य थे क्योंकि दर्शन ने इनी प्रगति की थी।

प्रशासन पर घटना को दबाने का आरोप

दर्शन के पिता रमेशभाई ने आरोप लगाया कि संस्थान के साथ-साथ अस्पताल के अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की। इसलिए उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही शब एक पोस्टमार्टम कर दिया गया। उन्हें नहीं

लगता कि यह आत्महत्या का मामला है, अगर आप सातवीं मजिल से गिरें तो आपको कई चोरे लगेंगी। लेकिन, पोस्टमार्टम के बाद जब मैंने अपने बेटे का चेहरा देखा तो मुझे कोई चोट के निशा नहीं दिखे। यह कैसे संभव है? और तो और, पोस्टमार्टम जल्दबाजी में किया गया और वह भी हमारी अनुमति के बिना, मुझे पोस्टमार्टम के बाद केवल उसका चेहरा देखने की अनुमति दी गई।

संस्थान प्रबंधन पर रुख
बदलने का आरोप

दर्शन की बहन जाहवी ने कहा कि उसके भाई की मौत के कारण अब तक साफ नहीं है। आईआईटी-बंबई प्रबंधन इस संबंध में लगातार अपना रुख बदलता रहा। जाहवी ने कहा कि उसका शब मेरे माता-पिता को न तो पोस्टमार्टम से पहले और न ही बाद में दिखाया गया। इससे पहले संस्थान ने हमें बताया था कि वह सीढ़ियों से गिर गया था। फिर प्रिसिपल ने हमें बताया कि मेरा भाई इमारत से कूद गया है। ऐसा लगता है कि उसके भाई की हत्या की गई है। दूसरी ओर, आईआईटी-बंबई ने मंगलवार को संस्थान में जातिगत पूर्वाग्रह के अरोपों को खारिज किया।

पालघर के लाघार सिटम और स्वास्थ्य सुविधाओं के खोखले दावे की फिर खुली पोल

7 घंटे तड़पती रही गर्भवती आदिवासी महिला, नहीं आए डॉक्टर, महिला और बच्चे की मौत



पालघर : पालघर की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की फिर एक बार पोल खुल गई है। जिसे के मनोर ग्रामीण अस्पताल में डॉक्टर के समय पर नहीं आने के कारण गर्भवती महिला घंटों प्रसव की पीड़ा से तड़पती रहीं और अंत में बच्चे की मौत गर्भ में ही हो गई। और महिला की भी जान नहीं बचाई जा सकी। जबकि इस दौरान गरीब परिवार जच्चा बच्चा की जान बचाने के लिए डॉक्टर और अधिकारियों की मिनते करते रहा। कई बार डॉक्टर को

फोन किया गया लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। चाहड़े निवासी अनीता वाघ को शुक्रवार सुबह प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद मनोर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती करने के बाद जब उसकी जान नहीं बचाई गयी तो पता चला कि महिला का सामान्य प्रसव संभव नहीं है। इसी बीच महिला की तबियत काफी बिगड़ गई तो उसे रेफर कर दिया गया। और उसे मुंबई या सिलवासा ले जाने के लिए कहा गया। मृतक महिला के एक परिजन ने कहा कि इसके बाद महिला को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद महिला को सिलवासा ले जाया जा रहा था लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही महिला और गर्भ में बच्चे की मौत हो गई। मनोर ग्रामीण अस्पताल की लापरवाही से आदिवासी महिला और उसके बच्चे की मौत के बाद एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में व्याप्त बदहाली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ठाणे के एक भवन में लगी आग, एक बच्चे समेत 13 लोगों की बचाई जा



ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे में बृहस्पतिवार को एक चार मंजिले भवन के इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स में आग लग जाने के बाद दो साल के एक बच्चे समेत 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नगर निकाय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ठाणे नगर निगम की क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन इकाई (आरडीएमसी) के प्रमुख अविनाश सावंत ने बताया कि चाराई क्षेत्र में इस भवन में सुबह कीरब साढ़े सात बजे आग लगी लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस भवन के भूतल पर एक बुक स्टोर है जबकि प्रथम तल पर दो दो कमरों का उपयोग किताबों के गोदाम के रूप में किया जाता है एवं चौथे तल पर एक मंदिर है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर दमकल की तीन गाड़ियां एवं पांच टैकर मौके पर भेजे गये। उनके अनुसार आरडीएमसी की एक टीम भी मौके पर पहुंची।

आवासीय परिसर में बिना कपड़ों के घूमी महिला, अश्वील हरकत करने पर मामल दर्ज



मुंबई : मुंबई के पूर्वी सांताक्रूज के रमन SRA को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी परिसर में सार्वजनिक रूप से अश्वील हरकत करने पर एक फ्लैट के मालिक और उसकी महिला मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। सोसाइटी के निवासियों की शिकायत के अनुसार पांचवीं मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति की महिला मित्र के पिछले सप्ताह इमारत में बिना कपड़ों के घूम रही थी। महिला पर सोसाइटी कंपाउंड में कई जगह अश्वील हरकत करने का आरोप है। घटना सोसाइटी के CCTV कैमरे में कैद हुई।

एक बिल्डिंग में परिवार और दूसरी बिल्डिंग में आरोपी रखता है महिला

सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि मकान मालिक सालों से अनजान लोगों को अपने फ्लैट में लाता है। उसे पहले भी ऐसा करने से मना किया गया है। वह अपने परिवार के साथ दूसरी बिल्डिंग में रहता है और इस बिल्डिंग में अपनी महिला मित्रों को लाता है। निवासियों ने शिकायत में बताया कि पहले भी वह महिला मित्रों के साथ सोसाइटी में अश्वील हरकत करते हुए पाया गया था, जिस पर काफी विवाद हो चुका है।



वसई विरार में
अनियमित जलापूर्ति से
नागरिक परेशान



विवर : वसई विरार शहर में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। वसई विरार शहर मनपा क्षेत्र के कई इलाकों में आठ से दस दिन के अंतराल में हो रही जलापूर्ति से लोग काफी परेशान हैं। पानी की किल्लत वाले इलाकों के लोग टैकर का पानी शुद्ध न होने से लोगों में हर बक्त बीमारी का भय बना रहता है। पानी की समस्या को लेकर मंगलवार को बहुजन विकास आधारी के संघटक सचिव अजीव पाटिल एवं पूर्व सभापति प्रशांत राउत के नेतृत्व में मनवेल पाड़ा के नागरिकों साथ पूर्व नगरसेविका चिरायु चोधरी, मिनल पाटिल, हेमांगी पाटिल, संगीता भेरे, रामाकांत पाटिल बाला पाटिल आदि का एक प्रतिनिधि मंडल ने वसई विरार मनपा आयुक्त अनिल कुमार पवार से मुलाकात कर लिखित पत्र देकर तत्काल समस्या को दर कराने की मांग किया है।

मुंबई में लगातार बढ़ रहे सेक्सटॉर्शन के मामले... रात में एक वीडियो कॉल और फिर लाखों की वसूली

मुंबई : मुंबई में सेक्सटॉर्शन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये गैंग कई लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और उनसे लाखों रुपये की वसूली कर रहे हैं। इस गैंग का शिकार ज्यादातर वो लोग हो रहे हैं जो अकेले रहते हैं या तो शादीशुदा नहीं हैं। इस गैंग के लोग ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन काफी ज्यादा शातिर हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच साइबर सेल के डीसीपी बालसिंह राजपूत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया ये गैंग सोशल मीडिया पर लोगों को मॉनिटर करती है खास बात ये है कि इस गैंग में जितने लोग हैं वो 10-12 तक ही पढ़े लिखे होते हैं।

ये लोग एक बार बातचीत करने के बाद सीधे वीडियो कॉल रात के समय करते हैं और अगर किसी ने कॉल उठा



लिया तो उसे न्यूड महिला का वीडियो दिखाई देता जिसे आप देख रहे होते हैं और वे लोग ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसे आपको भेजकर आपसे पैसे वसूलने लगते हैं। राजपूत ने बताया कि सेक्सटॉर्शन के मामले पिछले दो साल में बढ़े हैं। आकड़ों की मानें तो साल 2021 में ऐसे 54 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से 24 मामलों में 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन 24 मामलों में से 4 मामले ऐसे थे जिसमें विक्रिम के पास से 10 लाख

से ज्यादा की रकम वसूली गई थी। वहीं साल 2022 में कुल 77 मामले दर्ज हुए थे जिसमें से 30 मामलों में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन 77 मामलों में से 22 मामलों में विक्रिम से आरोपियों में 10 लाख से ज्यादा की रकम वसूल की थी। भारत में खासकर मुंबई में जितने भी सेक्सटॉर्शन के मामले सामने आए हैं, उसमें कॉल करने वाले आरोपी भरतपुर, अलवर (राजस्थान), मेवात (हरियाणा) या तो झारखण्ड से होते हैं। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में एक मामला उनके सामने आया है, जिसमें वेस्टर्न मुंबई में रहने वाले एक 71 साल के व्यापारी से इस गैंग से 51 लाख रुपये का सेक्सटॉर्शन किया गया है। इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

मुंबई में जली चलती लोकल ट्रेन, जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरे यात्री

मुंबई : हाल ही में आई बड़ी जानकारी के मुताबिक, मुंबई की एक लोकल ट्रैन जल गई है। दरअसल सेंट्रल रेलवे की हालत ऐसी हो गई है कि हर दिन किसी न किसी की मौत हो रही है। ऐसे में रेलवे व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि आज आसनगांव रेलवे स्टेशन के पास लोकल ट्रैन से अचानक धुआं निकलने लगा।



लगा, जिसके चलते यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी रोकी और नीचे उतर गए। ऐसे में हुआ यह कि भारी मात्रा में धुआं उठने के कारण यात्रियों में अफरातफरी मच गई। कई यात्री लोकल से नीचे कूद गए। पता चला कि ब्रेक में घर्षण के कारण लोकल के पहिए में आग लग गई। लेकिन इस हादसे को लेकर स्टेशन पर अफरातफरी मच गई, गर्नीमत यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई।

शिंदे-फडणवीस सरकार लगाएगी बॉलीबुड पर लगाम!

जल्द जारी होंगे
ये नियम...



महाराष्ट्र : एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार अब फिल्म उद्योग और मनोरंजन क्षेत्र में निर्माताओं और कलाकारों की मनमानी पर अंकुश लगाने जा रही है। क्योंकि सरकार ने फिल्म उद्योग में काम करने वाले अभिनेताओं और श्रमिकों के साथ-साथ निर्माता और निर्देशकों के लिए एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सरकार द्वारा नए नियम जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे।

ऐसा करने पर हो सकती है

गिरफ्तारी

बॉलीबुड सेक्टर में कई जगहों पर कर्मचारियों को समान वेतन नहीं मिलता है, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य सरकार के फैसले के बाद कलाकारों और कर्मचारियों का वेतन कानून के मुताबिक देना होगा। सरकार इसे भुगतान नहीं करने वाले

लागू होगी एसओपी

फिल्म निर्माताओं के पास श्रमिकों और कलाकारों की जिम्मेदारी होगी। फिल्म सीरियल, विज्ञापनों और वेब

सीरीज पर एसओपी लागू होगा। श्रमिकों और कलाकारों का शोषण रोकने के लिए एसओपी लागू की जाएगी। न्यूतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार वेतन देना अनिवार्य है। आपके सरकारी पोर्टल पर शिक्षायत दर्ज करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। सरकार द्वारा महिला श्रमिकों को गृह परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। इस बारे में आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से जल्द ही दी जाएगी। मायानगरी मुंबई में प्रसिद्ध फिल्म उद्योग के कारण मुंबई बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्योग में कई कर्मचारी और श्रमिक काम करते हैं। उन्हें वर्षों से कुछ समस्याएं हैं।

परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भड़की जितेंद्र आळ्हाड की पत्नी,



ठाणे : महाराष्ट्र के पूर्व आवास मंत्री और राकांपा नेता जितेंद्र आळ्हाड के परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। इस वजह से अब हड्डकंप मच गया है। वहीं, अब जितेंद्र आळ्हाड की पत्नी रीता ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है, जो करना है करो, अब अस्तित्व की लड़ाई है, यह मेरे परिवार की बात है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर सुधारण सिंह ठाकुर उर्फ बाबाजी को जितेंद्र आळ्हाड के परिवार को मारने के लिए सुधारण देने का एक ऑफिडियो क्लिप में बाबाजी के पैसों के लेनदेन के बारे में बात की गई है। इतने सबूत होने के बाद अब कानून के सो कॉल्ड लोग कहा है। गुरुवार की रात भी उन्होंने मुम्बई में हमारे पदाधिकारी को फोन किया और धमकी दी कि उनके पास आळ्हाड का नंबर है।

जितेंद्र आळ्हाड की पत्नी ने आगे कहा, कमिशन के तौर पर उनका करियर कैसा रहा है, यह सभी जानते हैं। सभी जानते हैं कि वह ब्ल्यू बॉय किसका है। पुलिस को अब कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो अब हमें कोर्ट

जाना पड़ेगा। वहीं से न्याय की उम्मीद है। हमें सुरक्षा प्रदान करने के बजाय उनकी हिम्मत कैसे हुई, क्या कोई उनपर दबाव बना रहा है? रीता ने आगे कहा, जो कुछ भी सामने आ रहा है, वो बेद बुरा है। कभी-कभी लोग नशे की हालत में शराब, सत्ता या पैसों के नशे में ऐसी बातें करते हैं। जो लोग हमेसा खबरों में रहते हैं, वो अक्सर ऐसी मानने की धमकी देते हैं, अब तक ठीक था। लेकिन, अब जो क्लिप वायरल हुई है उसमें महेश अहरी की आवाज 100% है या नहीं, इस बात की पुलिस जांच करें।